संभाग पोस्ट
साप्ताहिक
RNI: MPHIN/2015/60688
जिलों से संभाग तक का सच
email:sambhagpost@gmail.com
वर्ष-9 । अंक-37 । प्रति मंगलवार, इंदौर, 10 फरवरी 2026 से 16 फरवरी 2026 । । मूल्य- 2 रु. । पृष्ठ- 8

इंदौर कलेक्टर कार्यालय में जवाबदेही लापता..!

सूचना के अधिकार की उड़ती धज्जियां

सिस्टम के 'बाबूवाद' में दम तोड़ता कानून

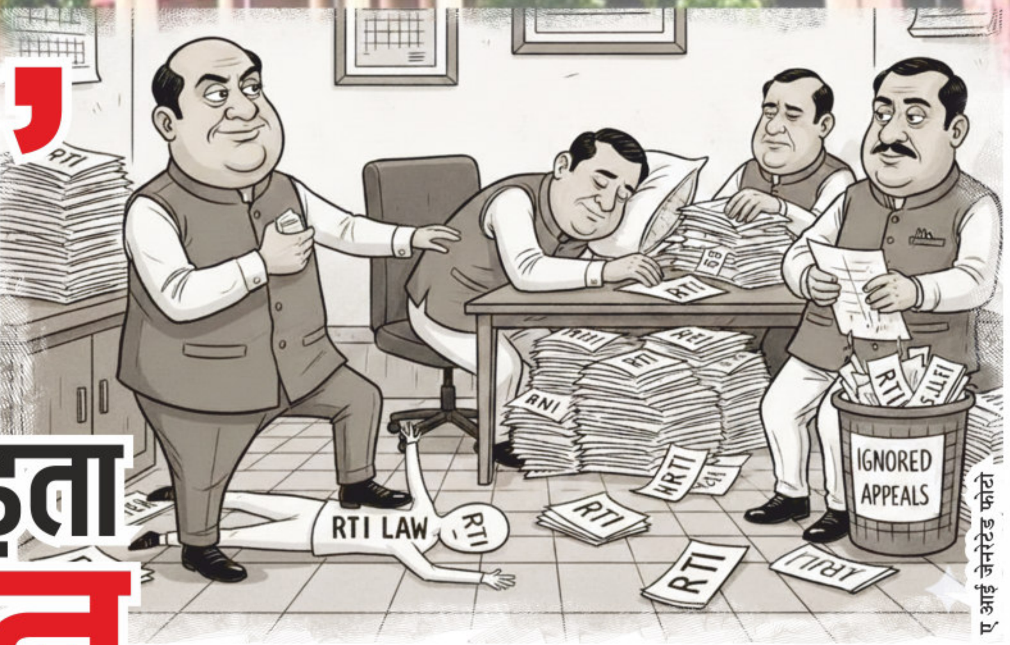

ए आई जेनरेटेड फोटो

SPECIAL REPORT

नवीन गलकर

इंदौर। लोकतंत्र में पारदर्शिता के लिए बना सूचना का अधिकार अब सरकारी दफ्तरों में धूल फांक रहा है। ताज़ा और शर्मनाक मामला कलेक्टर कार्यालय इंदौर से सामने आया है, जहाँ एक आवेदक को जानकारी देने के बजाय उसे दफ्तरों के अंतहीन चक्कर लगवाने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का खेल खेला जा रहा है। विडंबना देखिए कि जिस कार्यालय को पूरे जिले में कानून का पालन सुनिश्चित करना है, वही कानून की धज्जियां उड़ाने का केंद्र बन गया है।

आवेदक ने नियम से आवेदन किया, फीस भरी, दस्तावेज लगाए। जवाब में क्या मिला? एक फोन कॉल— 'अरे भाई साहब, ये कागज चाहिए दफ्तर आना पड़ेगा, जरा फलां मैडम से मिल लीजिए, फिर ढिकां सर से बात कर लीजिएगा।' वाह! क्या गजब की व्यवस्था है। शायद यहाँ के 'बाबू' आवेदक को दफ्तर बुलाकर 'शिष्टाचार' सिखाना चाहते हैं। आखिर ये कौन सी 'खास मैडम' हैं जिनसे मिले बिना फाइल का पहिया नहीं घूमता? क्या सूचना का अधिकार अब सरकारी दफ्तरों में 'दर्शन शास्त्र' बन गया है कि जब तक बाबू के दर्शन न हों, ज्ञान (जानकारी) प्राप्त नहीं होगा? इस तमाशे में जब संभाग आयुक्त कार्यालय ने कलेक्टर कार्यालय को पत्र लिखकर 'आवश्यक कार्यवाही' का निर्देश दिया। साधारण भाषा में कहें तो बड़े साहब ने छोटे साहब को काम करने को कहा। लेकिन कलेक्टर कार्यालय के शूरवीरों ने उस आदेश को भी ठेंगे पर रख दिया। जब ये लोग अपने ही वरिष्ठ अधिकारियों के पत्रों को कचरे के डिब्बे की शोभा बना सकते हैं, तो आम आदमी की हैसियत तो इनके लिए 'चींटी' से ज्यादा कुछ नहीं है। संभाग आयुक्त कार्यालय के निर्देशों को भी कलेक्टर कार्यालय के बाबुओं और अफसरों ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। न तो कोई कार्यवाही हुई और न ही आवेदक को सूचित करने की जहमत उठाई गई। यह सीधे तौर पर वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवमानना और प्रशासनिक अनुशासनहीनता का जीवंत प्रमाण है।

आवेदक को व्यक्तिगत रूप से बुलाकर मानसिक प्रताड़ना क्यों दी जा रही है? क्या यह जानकारी छिपाने या आवेदक को डराने की कोई सोची-समझी चाल है?

यह सिर्फ एक जिले की बीमारी नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश के सरकारी महकमों में यह 'कैंसर' की तरह फैल चुका है। जानकारी मत दो, और अगर देना भी पड़ जाय तो अधूरी और भ्रामक दो, उसे इतना थका दो कि वह जानकारी मांगना ही भूल जाए। अधिकांश कार्यालयों में आर.टी.आई. के नियमों का ऐसा 'मजाक' उड़ाया जा रहा है कि कपिल शर्मा का शो भी फीका पड़ जाए। तीस दिन की समय सीमा अब महज कागजों तक सीमित है। प्रथम अपील और द्वितीय अपील के बाद भी जानकारी न मिलना यह दर्शाता है कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं, जिसे छिपाने के लिए आर.टी.आई. कानून का ही गला घोंटा जा रहा है।

संभाग पोस्ट

सुविचार

सपनों की उड़ान वही भरते हैं, अकेले पंख हौसलों से बनते हैं।'

संपादकीय

लोकतंत्र के 'बाबू' और RTI की 'सुपारी'

'सूचना का अधिकार कानून' जिसने कभी आम आदमी को 'राजा' की कुर्सी के सामने सवाल पूछने की हिम्मत दी, वह आज खुद सरकारी दफ्तरों की धूल फांक रही फाइलों के नीचे दम तोड़ रहा है। हमारे देश के सरकारी कार्यालयों में एक नया 'महोत्सव' मनाया जा रहा है—'आर.टी.आई. दहन उत्सव' यहाँ नियम किताबों में उतने ही सुरक्षित हैं जितने कि तिजोरी में बंद पुराने सिक्के, जिनका चलन बाबूजी ने अपनी सुविधा के अनुसार बंद कर दिया है। लोक सूचना अधिकारी, जिन्हे नियम नहीं पता, प्रक्रिया नहीं पता,अगर कुछ पता है तो बस यह कि 'सूचना कैसे छुपानी है'। यह अनभिज्ञता प्राकृतिक नहीं है, यह प्रायोजित है। कानून की हत्या करने का सबसे आसान तरीका है—उसे नजरअंदाज करना। सूचना का अधिकार कानून का मूल उद्देश्य नागरिक को सशक्त बनाना था, लेकिन आज का तंत्र शायद इस 'सशक्तीकरण' से डर गया है। अधिकारियों को लगता है कि अगर जानकारी बाहर आ गई, तो उनके भ्रष्टाचार और अकर्मण्यता के किले ढह जाएंगे। इसलिए, प्रथम अपील से लेकर द्वितीय अपील तक की राह को इतना पथरीला बना दिया गया है कि आम आदमी थक हार कर बैठ जाए। जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली को देखकर लगता है कि वे सूचना के अधिकार का 'अंतिम संस्कार' करने पर तुले हैं। जिस कानून को लोकतंत्र की ढाल बनना था, उसे दफ्तरों का कूड़ादान बना दिया गया है। सरकार इन अधिकारियों के 'प्रशिक्षण' पर करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाती है। फाइव स्टार होटलों और वातानुकूलित कमरों में इन्हें सिखाया जाता है कि पारदर्शिता क्या है। लेकिन जैसे ही ये अधिकारी अपनी कुर्सी पर बैठते हैं, इन्हें 'स्मृतिभ्रंश' की बीमारी हो जाती है। यदि सरकार और प्रशासन वाकई गंभीर हैं, तो उन्हें केवल प्रशिक्षण पर खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि उन अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो जानबूझकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वरना, वह दिन दूर नहीं जब सूचना का अधिकार केवल इतिहास की किताबों में एक 'मृत कानून' के रूप में पढ़ाया जाएगा।

- नवीन गलकर

कथित समाजसेवी निकला गुंडा

थाने में एफआईआर दर्ज

■ **इंदौर । संभाग पोस्ट**

जयरामपुर कॉलोनी, इंदौर निवासी सन्नी परियानी द्वारा कथित रूप से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सन्नी परियानी द्वारा एक आवासीय मकान पर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया गया, जिसको लेकर संबंधित पक्ष द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। इस शिकायत के आधार पर पुलिस थाना अन्नपूर्णा द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के विरुद्ध गैर-जमानती धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है तथा विधि अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उल्लेखनीय है कि सनी परियानी स्वयं को सिंधी समाज में समाजसेवी के रूप में प्रस्तुत करता रहा है, किंतु इस घटना के बाद समाज में भी प्रश्नचिह्न खड़े हो रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि समाजसेवा के नाम पर किसी भी प्रकार की अवैध या आपराधिक गतिविधि को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रशासन से मांग की जा रही है कि मामले की निष्पक्ष एवं शीघ्र जांच कर दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि कानून का भय बना रहे और आमजन का विश्वास कायम रह सके।

जहरीले बयान से विषैले पानी तक कटघरे में एमपी की सरकार

नरेंद्र तिवारी
'स्वतंत्र लेखक'
7 ,शंकर गली मोतिबाग
सेंधवा जिला बड़वानी मप्र।
मोबा-9425089251

किसी भी सरकार की दृढता और जन सामान्य से जुड़े विषयों में उसकी संवेदनशीलता सरकार की कीर्ति, ख्याति और गुणगान का महत्वपूर्ण आधार होती है। इस लिहाज से मध्यप्रदेश राज्य सरकार जिसने अपने नवीन नैतृत्व के साथ दो बरस से अधिक की कार्य अवधि पूर्ण कर ली है, अब यह जानना बहुत जरुरी हो जाता है की जनसामान्य से जुड़े आवश्यक विषयों के प्रति सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री, नेता और अफसरों का दृष्टिकोण क्या है? जब किसी राज्य में केंद्रीय नैतृत्व ने नव प्रयोग करते हुए वरिष्ठता के क्रम को उलांघकर मोहन यादव को मध्यप्रदेश की सरकार का मुखिया बनाया हो, तब राज्य सरकार का मूल्यांकन और भी जरुरी हो जाता है। सरकार के कार्यो का मूल्यांकन जनता की नजर से करने का पैमाना वैसे तो पांच बरस में होने वाले चुनाव है। इस पैमाने पर अब से दो बरस पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नैतृत्व में एमपी की जनता ने भाजपा को व्यापक जन समर्थन देकर राज्य में राज्य में पांच वर्षीय कार्यकाल सौपा है, जनादेश इतना बड़ा की बहुमत से 50 सीटें अधिक याने की 230 में से 163 सीट जीतकर भाजपा ने इतिहास रचा। किंतु यह सफलता भाजपा को पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान के नैतृत्व में प्राप्त हुई थी। शिवराज के नैतृत्व में भाजपा को मिले व्यापक जन समर्थन के बाद भाजपा हाईकमान ने शिवराज के स्थान पर महाकाल की नगरी उज्जैन दक्षिण के विधायक एमपी सरकार के पूर्व शिक्षामंत्री मोहन यादव को प्रदेश की कमान सौपी। मध्यप्रदेश में मोहन यादव ने 13 दिसम्बर 2023 को राज्य के 19 वें मुख्यमंत्री के रुप में शपथ ग्रहण की थी।

मध्यप्रदेश जिसकी बागडोर शिवराज के हाथों से मोहन यादव के हाथों में आ चुकी थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री के रुप में अपने शुरुवाती निर्णयों में मोहन यादव सरकार की दृढता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उन्होंने पदभार ग्रहण करते ही 13 दिसम्बर 2023 को धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर निर्धारित डेसिबल से अधिक तेज आवाज वाले लाउडस्पीकरों और डीजे के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया। यह कदम सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत ध्वनि प्रदूषण कम करने और जन स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए उठाया गया था। इस निर्णय को सम्पूर्ण प्रदेश में समान रुप से लागू करने में भी सफलता प्राप्त हुई थी। जब गाँव-गाँव, शहर-शहर ऊँचे स्थानों पर लाउड स्पीकर लगाकर धार्मिक कट्टरवाद की प्रतिस्पर्धा का दौर चल रहा था। मोहन यादव की सरकार ने आमजनता के हित में दृढता से कदम उठाया। उक्त निर्णय को समान रुप से लागू भी किया। तेज आवाज से परेशान आमजन को राहत देने का काम किया था। एमपी की सरकार का दूसरा कठोर निर्णय परिवहन चैक पोस्ट समाप्त करने का था। जिसका आधिकारिक निर्णय 30 जून 2024 को लिया गया। और यह 1 जुलाई 2024 से पुरे राज्य में लागू भी हो गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अंतर प्रांतीय सीमाओं पर होने वाली अवैध वसूली को रोकने और गुजरात मॉडल अपनाने के लिए चेक पोस्ट को बंद करने का कड़ा फैसला लिया था। यह फैसला सरकार का भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार था। जनता से जुड़े कठोर निर्णय लेने वाली मोहन सरकार कुछ मामलों में अनिर्णय का शिकार होती दिखी, जिन विषयों पर संवेदनशीलता और दृढता दिखाए जाने की आवश्यकता थी, राज्य सरकार और उसके मुखिया खामोश नजर आए। ऐसा ही राष्ट्रीय अस्मिता से जुडा मामला एमपी सरकार के जनजातीय कार्यमंत्री के रुप में विजय शाह द्वारा दिया गया बयान था। उन्होंने भारतीय सेना की कर्नल सौफिया कुरैशी जिन्होंने आपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की कार्यवाही से दुनियाँ को अवगत कराया स्वयं भी कार्यवाही का हिस्सा रही। उन पर दिए जहरीले बयान में मंत्री विजय शाह ने उन्हें आंतकियों की बहन कहकर सम्बोधित किया। भारत राष्ट्र की जिस नायिका पर देश गौरव कर रहा है, एमपी सरकार के जिम्मेदार मंत्री द्वारा दिए बयान ने मध्यप्रदेश की जनता को शर्मन्दगी से भर दिया था, उनका यह बयान देश की गरिमा को नुकसान पहुंचाने वाला है, किंतु आश्चर्य की 10 माह होने को आए मंत्री अपने पद पर बना हुआ है। एमपी की सरकार उन्हें मंत्री पद से हटाने में नाकाम दिखाई दी, जब से अब तक का हर दिन एमपी की सरकार और उसके मुख्यमंत्री की संवेदना और दृढता को मुंह चिढ़ाता प्रतीत हो रहा है।

एमपी की आर्थिक राजधानी इंदौर जिसे देश के सबसे साफ शहर का तमगा मिला हुआ है। अभी वर्ष 2026 की जनवरी माह में इस शहर के भागीरथ पूरा इलके में विषैले पानी से फैले डायरिया के कारण एक के बाद एक 33 लोगो की मौत हो गयी। मौत का क्रम अभी भी जारी है, जाने कब रुकेगा, सरकार ने तीन अधिकारियो को निलंबित किये जाने एवं मृतक परिवार को मुआवजे के रुप में मात्र 2 लाख रु की घोषणा कर इस गंभीरतम अपराध पर पर्दा डालने का प्रयास किया। इस अति गंभीर विषय पर प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री ने एक पत्रकार को दिए बयान में फोकट प्रश्न और घंटा जैसे शब्दों के इस्तेमाल ने प्रदेश की जनता को झकझोर दिया। इस बयान ने प्रदेश को गहरे रुप से शर्मिंदा किया। एमपी के इंदौर में विषैले पानी से हुई मौत के सम्पूर्ण घटनाक्रम पर सरकार संवेदन शून्य नजर आई। यह विषय प्रदेश के विपक्ष को सरकार पर हमलावर होने का मौका था, विपक्ष ने ऐसा ही किया। सरकार और मुख्यमंत्री विपक्ष को दोष देते दिखे। इस अति गंभीर विषय पर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा की फायर ब्राड नेता उमा भारती का बयान काबिले गौर रहा, जिसमे जनमत की आवाज सुनाई दी उन्होंने पर अपनी पोस्ट में लिखा ' सिर्फ इंदौर के मेयर ही नहीं, मध्यप्रदेश का शासन एवं प्रशासन कटघरे में खडे है, इस महापाप के सभी जिम्मेदार लोग जनता के प्रति अपराध के कटघरे में खडे है, उमा भारती ने लिखा इंदौर दूषित पानी के मामले में यह कौन कह रहा है की हमारी चली नहीं, जब आपकी चली नहीं तो आप पद पर बैठे बीसलेरी का पानी क्यों पीते रहे? जनता के बिच क्यों नहीं गए? ऐसे पापों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता या तो प्रायश्चित या दंड!' उमा भारती की इस पोस्ट में सरकार को सख्त कदम उठाने का संदेश था। किंतु सत्तामद में चूर प्रदेश सरकार इस संवेदनशील विषय पर असंवेदनशील नजर आई। घटनाक्रम तो प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार, राशन माफिया, शराब माफिया, बढ़ती बेरोजगारी, लालफीताशाही भी है,किंतु आपरेशन सिंदूर की नायिका सौफिया कुरैशी पर मंत्री विजय शाह के बयान के बाद भी उनका पद पर बने रहना? इंदौर के भागीरथ पूरा में विषैले पानी से हुई 33 लोगो की मौत के बाद सरकारी तंत्र की कमी, सरकारी दृढता का अभाव, प्रदेश सरकार के मुखिया मोहन यादव जो अपने आरम्भिक कुछ महीनों में कठोर निर्णय लेते दिखे, बाद में अनिर्णय का शिकार हो गए। विषैले पानी और जहरीले बयान के बाद सरकार के कमजोर फैसलों ने एमपी सरकार के मुखिया और सरकार की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव को जरूरत है, संवेदनशील विषय पर कठोर रुख इख़्तियार करने की, हाई कमान एक बार मौका देता है, बाद में प्रदेश की जनता आपको मजबूत लीडर के रुप में देश के सामने प्रस्तुत करती है। जनता का नेता बनने के लिए जरूरत है। जनभावना के सम्मान की एमपी की सरकार और उसके मुखिया मोहन यादव को समय रहते जनता की भावना का आदर करना सीखना होगा। हर विषय पर दिल्ली की और देखना भी आपकी कमजोरी और निर्णय लेने में देरी को प्रदर्शित करते है।

अब 72 घंटे में ईमेल पर मिलेगा मृत्यु प्रमाण पत्र, नगर निगम की नई व्यवस्था

■ इंदौर । संभाग पोस्ट

इंदौर नगर निगम ने नागरिकों को बड़ी राहत देने वाली नई व्यवस्था लागू की है। अब घर पर होने वाली मृत्यु के मामलों में मृत व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र 72 घंटे के भीतर परिजनों के ईमेल पर भेजा जाएगा। इसके लिए नगर निगम कार्यालय के चक्कर लगाने या किसी तरह का आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी।

पहले घर भेजा जाता था प्रमाण पत्र

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि पहले नगर निगम की ओर से मृत्यु होने पर 72 घंटे के भीतर शोक संदेश के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र मृतक के घर भिजवाया जाता था। बाद में जन्म-मृत्यु के राष्ट्रीय पोर्टल से नगर निगम पोर्टल के जुड़ने के कारण यह व्यवस्था बंद हो गई थी।

संशोधित रूप में फिर लागू हुई व्यवस्था

महापौर ने बताया कि अब राष्ट्रीय पोर्टल से जुड़े रहते हुए इस व्यवस्था को संशोधित स्वरूप में फिर से लागू किया गया है। मुक्तिधाम पर अंतिम संस्कार के समय यदि यह जानकारी दी जाती है कि संबंधित व्यक्ति की मृत्यु घर पर हुई है, तो परिजनों द्वारा दिए गए ईमेल एड्रेस पर 72 घंटे के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र भेज दिया जाएगा।

नगर निगम आने की जरूरत नहीं

इस नई व्यवस्था के तहत मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए परिजनों को नगर निगम कार्यालय आने, आवेदन करने या किसी तरह का शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। नगर निगम ने ईमेल के माध्यम से प्रमाण पत्र भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

अस्पताल में मृत्यु पर लागू नहीं होगी सुविधा

प्रश्न के उत्तर में महापौर ने स्पष्ट किया कि अस्पताल में होने वाली मृत्यु के मामलों में यह सुविधा फिलहाल लागू नहीं हो पाएगी। इसका कारण यह है कि अस्पतालों से मृत्यु की जानकारी नगर निगम को विलंब से प्राप्त होती है, जिससे 72 घंटे के भीतर प्रमाण पत्र जारी करना संभव नहीं हो पाता।

जन्म प्रमाण पत्र की व्यवस्था पहले से लागू

जन्म प्रमाण पत्र को लेकर उन्होंने बताया कि जिन अस्पतालों में प्रसूति होती है, वहां से जन्म प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था पहले से ही लागू है। इसे तत्काल व्यवस्था में परिवर्तित करना अभी संभव नहीं है।

हर साल जारी होते हैं हजारों मृत्यु प्रमाण पत्र

इंदौर नगर निगम द्वारा हर वर्ष औसतन 14 हजार मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। वर्ष 2026 में अब तक 1084 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। वर्ष 2025 में 15314, 2024 में 14119, 2023 में 13461 और 2022 में 14237 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए थे।

इंदौर में डेढ़ लाख पशुओं को लगेंगे टीके, डेटा भी होगा ऑनलाइन

■ इंदौर । संभाग पोस्ट

पशुओं के टीकाकरण और कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं को पारदर्शी बनाने के लिए पशुपालन एवं डेरी विभाग ने नई डिजिटल व्यवस्था लागू की है। इस व्यवस्था के तहत अब टीकाकरण के बाद पशुपालक को ओटीपी बताना होगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सही पशुपालक के सही पशु को ही टीका लगाया गया है।

एफएमडी टीकाकरण अभियान 15 फरवरी तक

प्रदेशभर में खुरपका मुंहपका रोग (फुट एंड माउथ डिजीज) से बचाव के लिए एफएमडी टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इंदौर जिले में यह अभियान 1 जनवरी से शुरू हुआ है, जो 15 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान जिले में करीब डेढ़ लाख पशुओं को एफएमडी का टीका लगाया जाना है।

आधार और ओटीपी से होगा सत्यापन

अभियान को डिजिटल करते हुए विभाग द्वारा हर पशुपालक का आधार नंबर लेकर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। 15 फरवरी से टीकाकरण के बाद वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी दर्ज करना अनिवार्य होगा। ओटीपी के माध्यम से यह पुष्टि होगी कि टीकाकरण वास्तविक लाभार्थी के पशु को ही किया गया है। यह पूरा डाटा भारत पशुधन ऐप पर सुरक्षित रूप से दर्ज किया जा रहा है।

अब तक 30 प्रतिशत पशुओं का टीकाकरण पूरा

अभियान के तहत इंदौर जिले में गाय, भैंस, भेड़ और बकरियों सहित लगभग डेढ़ लाख पशुओं को टीके लगाए जाने हैं। विभाग के अनुसार अब तक जिले में करीब 30 प्रतिशत पशुओं का टीकाकरण पूरा किया जा चुका है।

84 एवीएफओ की ड्यूटी, टैगिंग भी अनिवार्य

उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं इंदौर डॉ. दिनकरराव पाटिल ने बताया कि अभियान के लिए जिले में 84 एवीएफओ की ड्यूटी लगाई गई है। इनके साथ क्षेत्रीय मैत्री और गोसेवक कार्यकर्ता भी तैनात हैं। टीकाकरण के दौरान पशुओं के कान में टैग लगाना अनिवार्य है। जिन पशुओं में टैग नहीं है, उन्हें टैग कर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और पूरा डाटा डिजिटल रूप से अपलोड किया जा रहा है।

खुरपका मुंहपका रोग से होता है भारी आर्थिक नुकसान

खुरपका मुंहपका रोग इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है, लेकिन पशुधन के लिए यह गंभीर और आर्थिक रूप से नुकसानदायक बीमारी है। देशभर में इसके मामले सामने आते रहते हैं, इसी कारण हर साल बड़े स्तर पर यह टीकाकरण अभियान चलाया जाता है।

आठवें वेतन आयोग के नाम पर साइबर ठगी से सावधान

इंदौर पुलिस क्राइम ब्रांच की आम जनता को सख्त चेतावनी

■ इंदौर । संभाग पोस्ट

आठवें वेतन आयोग को लेकर सरकारी एवं निजी कर्मचारियों में सैलरी बढ़ोतरी और एरियर की गणना को लेकर उत्सुकता बढ़ती जा रही है। इसी का फायदा उठाकर साइबर अपराधी ठगी के नए-नए हथकंडे अपना रहे हैं।

इंदौर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी करते हुए आम नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है।

क्राइम ब्रांच के अनुसार, साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप, टेलीग्राम व अन्य डिजिटल माध्यमों से फर्जी लिंक और APK फाइल भेज रहे हैं। इन लिंक के जरिए आठवें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ने, एरियर चेक करने या कैलकुलेशन दिखाने का लालच दिया जा रहा है।

जैसे ही कोई व्यक्ति इन लिंक पर क्लिक करता है या APK फाइल इंस्टॉल करता है, उसका मोबाइल फोन साइबर अपराधियों के नियंत्रण में चला जाता है, जिससे बैंक अकाउंट, ओटीपी, निजी डाटा और पैसे चोरी होने की आशंका बढ़ जाती है।

पुलिस की अपील

किसी भी अनजान मैसेज, लिंक या APK फाइल पर क्लिक न करें

सैलरी या वेतन आयोग से संबंधित जानकारी केवल सरकारी वेबसाइट से ही प्राप्त करें

मोबाइल में अनजान ऐप इंस्टॉल करने से बचें

किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करें

इंदौर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वेतन आयोग से जुड़ी कोई भी आधिकारिक जानकारी सोशल मीडिया लिंक या APK फाइल के माध्यम से नहीं भेजी जाती।

सतर्क रहें, सुरक्षित रहें – इंदौर पुलिस

सीएम हेल्पलाइन पर सीएस की रिपोर्ट

10 विभागों के अफसरों का डी-कैटेगरी परफॉर्मेंस

शिकायतों का क्या रहा हाल? यहां देखिए डाटा

■1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक कुल शिकायतें- 3 लाख 97 हजार ■संतुष्टि के साथ बंद की गई शिकायतें- 2 लाख 4206 ■स्पेशल क्लोज- 730 ■नॉट कनेक्टेड और बंद करने की 30 शिकायतें ■कार्यक्षेत्र से बाहर 3782 शिकायतें ■आंशिक बंद 3900 शिकायतें ■लंबित 179439 शिकायतें

■ **भोपाल । संभाग पोस्ट**

मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव ने पिछले दिनों समीक्षा अफसरों की समीक्षा बैठक की थी. कलेक्टर कमिश्नर स्तर के अधिकारी भी बैठक में शामिल थे. जिसके बाद एक और समीक्षा खुद मुख्य सचिव कार्यालय ने की है. सीएम हेल्पलाइन की रिपोर्ट के आधार पर 10 विभागों के बड़े अधिकारियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट डी कैटेगरी की आई है. यह ऐसे विभाग हैं, जिनको लेकर जनता से जुड़े हुए काम अक्सर होते हैं. मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में पहुंचने के बाद अफसरों को शिकायतों का निराकरण करना था, लेकिन रवैया यह रहा कि शिकायतें दम तोड़ रही हैं. उनका निराकरण नहीं हुआ है.

मुख्य सचिव कार्यालय के मुताबिक 10 विभागों की समीक्षा पिछले दिनों की गई थी. जनवरी 2026 की समीक्षा बैठक में कई ऐसे विभाग हैं, जो जनता से जुड़े हुए हैं. लेकिन उनमें कारवाई काफी कम हुई है. पंचायत, लोक निर्माण विभाग, पिछड़ा और अल्पसंख्यक, जल संसाधन, जनजाति अनुसूचित जाति कल्याण, राजस्व उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग का रिकॉर्ड डी कैटेगरी के मुताबिक आया है. जानकारी के मुताबिक इन विभागों में 50इ से कम और 27 प्रतिशत रहा है. यानी कि शिकायतें विभाग तक पहुंची उनका निराकरण नहीं हुआ. अधिकांश शिकायतों का निराकरण 50 दिन की भीतर भी नहीं हुआ है.

६० दिन बाद भी नहीं हुआ निराकरण

60 दिन बाद भी शिकायत जस की तरफ पड़ी हुई है. खास बात है कि नीचे स्तर से शिकायत का निराकरण न होने पर यह शिकायत प्रमुख सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव तक पहुंचती है. इसके बाद भी अधिकारियों का रवैया है कि जनता की शिकायतों का निराकरण हो ही नहीं रहा है. उन्हें इस बात की भी चिंता नहीं है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन तक शिकायत पहुंचना यानी मुख्यमंत्री सचिवालय और मुख्यमंत्री के संज्ञान में है. फिर भी जनता से जुड़ी हुई शिकायतों का निराकरण नहीं हो रहा है.

इन अधिकारियों के विभागों का कामकाज रहा खराब

जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी डॉ राजेश अजोरा का है लेकिन सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों का अंबार लगा हुआ है. हायर एजुकेशन विश्वविद्यालय की समस्या भी जमकर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन तक पहुंच रही है. इस विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपम राजन है. सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय कुमार शुक्ला है. यहां पर भी शिकायतों के निराकरण का हिसाब किताब खराब है. कड़क मिजाज महिला अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपाली रस्तोगी के विभाग पंचायत का बेहतर नहीं है. लोक निर्माण विभाग का भी यही हाल है. इसके साथ ही नामांकन सीमांकन बंटवारे और अन्य किसानों की समस्या से जुड़े हुए विभाग राजस्व की जिम्मेदारी प्रमुख सचिव विवेक कुमार पोरवाल की है. उनके भी विभाग की यही स्थिति है. खराब परफॉर्मेंस वाली सूची में इसलिए टॉप टेन में शामिल है.

आईडीए का हाल बेहाल

1000 करोड़ के काम चल रहे 2000 करोड़ के शुरू होंगे

इंजीनियर 106 होने चाहिए लेकिन है सिर्फ 30

■ **इंदौर । संभाग पोस्ट**

इंदौर के विकास का जिम्मा संभालने वाली एजेंसी इन दिनों खुद ही अपनी आधारभूत संरचना के संकट से गुजर रही है। एक तरफ जहां शहर में हजार करोड़ रुपये के विकास कार्य चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इन कार्यों की निगरानी और गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाला तंत्र बेहद कमजोर नजर आ रहा है। हालात यह हैं कि करोड़ों के प्रोजेक्ट्स बिना पर्याप्त तकनीकी देखरेख के आगे बढ़ रहे हैं। जानकारी के अनुसार, विकास प्राधिकरण के पास इस समय करीब 1000 करोड़ रुपये की लागत के प्रोजेक्ट्स जमीनी स्तर पर चल रहे हैं। इसके अलावा, आने वाले समय में लगभग 2000 करोड़ रुपये की नई परियोजनाओं की शुरुआत होनी है। इतनी बड़ी राशि और जिम्मेदारी होने के बावजूद, एजेंसी के पास इंजीनियरों और तकनीकी स्टाफ की भारी कमी है।

जिम्मेदारियों का बोझ और खाली कुर्सियां

किसी भी निर्माण एजेंसी की रीढ़ उसके इंजीनियर होते हैं, लेकिन यहाँ स्थिति चिंताजनक है। आईडीए को अभी 106 इंजीनियर की जरुरत है लेकिन फिलहाल उसके पास मात्र 30 इंजीनियर ही है। सरकार को पिछले तीन सालों में 12 बार पत्र लिखे जा चूका है लेकिन उसके बाद भी कोई समाधान नहीं है। आईडीए की हालत इतनी खराब है की स्वीकृत 386 इंजीनियर, अफसर, बाबुओं में से सिर्फ 124 कर्मचारी ही बचे है।

नियमानुसार बड़े प्रोजेक्ट्स की निगरानी के लिए हर स्तर पर कनिष्ठ यंत्रियों से लेकर कार्यपालन यंत्रियों तक का एक पूरा ढांचा होना चाहिए। वर्तमान में चल रहे प्रोजेक्ट्स की संख्या और उनके बजट के मुकाबले उपलब्ध स्टाफ ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीकी अमले की कमी का सीधा असर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समय सीमा पर पड़ता है। जब एक ही इंजीनियर के पास क्षमता से अधिक साइट्स की जिम्मेदारी होती है, तो नियमित निरीक्षण संभव नहीं हो पाता। इसका खामियाजा अंततः शहर की जनता को खराब गुणवत्ता वाली सड़कों और इमारतों के रूप में भुगतना पड़ता है।

भविष्य की योजनाओं पर सवालिया निशान

एजेंसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन 2000 करोड़ रुपये के नए प्रोजेक्ट्स को शुरू करने की है जो पाइपलाइन में हैं। जब वर्तमान में चल रहे कार्यों की ही ठीक से मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है, तो नए कार्यों का बोझ यह ढांचा कैसे उठा पाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक, लंबे समय से रिक्त पदों पर भर्ती नहीं होने और प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों के वापस जाने से यह संकट गहराया है। प्रशासनिक स्तर पर बार-बार मांग उठाने के बावजूद अभी तक पर्याप्त संख्या में तकनीकी स्टाफ की तैनाती नहीं हो सकी है। ऐसे में शहर के सुनियोजित विकास का सपना फाइलों और वादों के बीच उलझता दिखाई दे रहा है।

इस बार गर्मी में तैराक लगा सकेंगे नेहरू पार्क के स्विमिंग पूल में छलांग

■ **इंदौर । संभाग पोस्ट**

देश को राष्ट्रीय स्तर के कई खिलाड़ी देने वाले इंदौर के नेहरू पार्क स्विमिंग पूल का कायाकल्प अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। अप्रैल तक यह फिर से तैराकी सीखने वालों के लिए खोल दिया जाएगा। पूल का डायविंग टावर बन चुका है और पूल में टाइल्स लगाने का काम भी हो रहा है। महापौर ने हाल ही में निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इसका निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा कर इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाए ताकि गर्मियों के सीजन में शहरवासियों को इसका लाभ मिल सके। लगभग चार करोड़ रुपये की लागत से हो रहे इस जीर्णोद्धार कार्य में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है। इस पूल को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया गया है, बल्कि यहां डाइविंग टावर और फिल्टरेशन प्लांट को भी अपग्रेड किया गया है। इसके अलावा परिसर में एक नई लाइब्रेरी और जिम जैसी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं, जिससे यह केवल एक स्विमिंग पूल न रहकर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में उभरेगा। सुरक्षा के लिहाज से पूल की गहराई को अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें बच्चों और नए सीखने वालों के लिए कम गहरा हिस्सा और पेशेवर तैराकों के लिए गहरा हिस्सा तय किया गया है। इसकी गहराई बीस फीट से ज्यादा रहेगी। पहले की तरह रियायती दरों पर सदस्यता दी जाएगी। महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से विशेष बैच भी संचालित किए जाएंगे। तय समयसीमा से ज्यादा समय इसके निर्माण में बीत चुका है, क्योंकि निर्माण एजेंसी ने टावर के पहले पूल की टाइल्स लगा दी थी, जो टावर निर्माण का मलबा गिरने के कारण टूट गई थी। उधर पूल भरने में भी एक सप्ताह से ज्यादा का समय लगेगा। पूल में 100 टैंकर से ज्यादा पानी लगेगा।

चोइथराम इंटरनेशनल एन आईबी वर्ल्ड स्कूल में गूंजा स्क्वैश का जोश

■ इंदौर। संभाग पोस्ट

शहर में पहली बार आयोजित इंदौर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का सफल आयोजन 8 फरवरी को चोइथराम इंटरनेशनल एन आईबी वर्ल्ड स्कूल, चोइथराम स्पोर्ट्स अकादमी एवं इन्फिनिटी अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। यह इंदौर का पहला ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट रहा, जिसमें अंडर-7 से लेकर मेन्स डबल्स तक विभिन्न आयु वर्गों में मुकाबले खेले गए।

टूर्नामेंट में बड़ी संख्या में उभरते खिलाड़ियों ने भाग लिया। छोटे बच्चों से लेकर जूनियर स्तर के खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट खेल, अनुशासन और खेल भावना से सभी का दिल जीत लिया। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धात्मक मंच प्रदान करना एवं इंदौर में स्क्वैश खेल को बढ़ावा देना रहा।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि, आयोजक, प्रशिक्षक, अभिभावक एवं खिलाड़ी उपस्थित रहे। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा—

'चोइथराम इंटरनेशनल एन आईबी वर्ल्ड स्कूल में आयोजित पहले इंदौर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का हिस्सा बनना हमारे लिए गर्व की बात है। हम आयोजकों व प्रायोजकों का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने खिलाड़ियों को यह मंच प्रदान किया। सभी प्रतिभागियों को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं।'

गर्ल्स अंडर-१७ में रोमांचक मुकाबला

गर्ल्स अंडर-17 वर्ग में शुभी गुप्ता एवं पाखसलिका के बीच फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। शुभी ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया, लेकिन अंततः पाखसलिका विजेता रहीं।

टूर्नामेंट विजेता

मिक्स्ड अंडर-७

प्रथम – देवांश
द्वितीय – रिधान

गर्ल्स अंडर-९

प्रथम – यशस्वी
द्वितीय – अनिका
तृतीय – विहा
चतुर्थ – तक्श्वी

बॉयज़ अंडर-९

प्रथम – युवान बांदी
द्वितीय – अथर्व मित्तल

तृतीय – सूर्यांश सिंह तोमर
चतुर्थ – सानी खंडेलवाल

गर्ल्स अंडर-११

प्रथम – गुरशीर
द्वितीय – आराध्या
तृतीय – यतिक्षा
चतुर्थ – मीरा

बॉयज़ अंडर-११

प्रथम – हर्षवीर पाहवा
द्वितीय – लक्ष्य अग्रवाल
तृतीय – हुसैन देवासवाला
चतुर्थ – अथर्व मित्तल

गर्ल्स अंडर-१४

प्रथम – शरण्या
द्वितीय – अनाया
तृतीय – एरिका
चतुर्थ – अनाया

बॉयज़ अंडर-१४

प्रथम – नक्षत्र गंगवानी
द्वितीय – युवराज

आयोजकों ने सभी विजेताओं एवं प्रतिभागियों को बधाई देते हुए भविष्य में भी ऐसे टूर्नामेंट आयोजित करने की प्रतिबद्धता जताई। यह आयोजन इंदौर में स्क्वैश खेल को नई पहचान देने वाला साबित होगा।

संभाग पोस्ट सामाजिक दृढ़ता संकल्प अभियान

अब आपकी आवाज होगी बुलंद लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के संग

आज के समाज में हम देख रहे हैं की शहरी परिवेश की बात करें या ग्रामीण परिवेश की आज के परिवेश में व्यक्ति अकेला पड़ता जा रहा है। आधुनिक तकनीकियों का इस्तेमाल करते-करते अपने आप को अकेला महसूस करता है, जब उसके ऊपर ऐसी कोई विपत्ति आती है की जब उसके परिवारजन या मित्र बंधु उसका साथ दे। तब वह पता है कि वह अकेला खड़ा है। यह आज के समाज का सत्य है। यह भारत के ७० प्रतिशत लोगों की सच्चाई है वह किसी भी प्रकार की समस्या में हो चाहे पारिवारिक या मानसिक, सामाजिक, प्रशासनिक या चिकित्सकीय हो ऐसी किसी भी समस्या में वह पाता है कि वह अकेला है। और यदि ऐसे मे किसी मोड़ पर कुछ व्यवधान उत्पन्न हो तब वह नीरस हो जाता है, और किसी न किसी प्रकार की गलती कर बैठता है। समाज की ऐसी सबसे बड़ी समस्या को लेकर हमने सामाजिक दृढ़ता संकल्प का अभियान चलाया है जिसके तहत हम उन सभी ऐसे लोगों के साथ खड़े हुए हैं जो हमसे जुड़ेंगे तथा वे लोग जो हमसे किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं, हमारा प्रयास यह होगा कि ऐसी किसी भी समस्या में हम उनके साथ खड़े हो जिस जगह पर वह सही है और उन्हें व्यवधान,समस्या का सामना करना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में संभाग पोस्ट परिवार उनके साथ खड़ा है।

- समाज में एक कहावत प्रचलित है सत्य परेशान हो सकता है। पराजित नहीं हो सकता,
- ईश्वर की इसी प्रेरणा को हमारे मीडिया चैनल हमारे अखबार ने आत्मसात किया है और हम उन सभी समाज जनों के साथ खड़े हैं जिनके साथ सत्य है।
- ईश्वर सत्य का साथ देने वाले उनके अनुयायियों की सहायता करने स्वयं नहीं आते किंतु किसी न किसी माध्यम से सत्य का साथ दे रहे व्यक्ति की सहायता जरूर करते हैं।
- हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि हमने यह मुहिम चलाई है जिसके तहत यदि आपके साथ सत्य है तो हम आपके साथ सदा खड़े हुए हैं
- हमारे चैनल और हमारे अखबार से जुड़े हुए सभी सदस्य गण जिनकी किसी भी प्रकार की परेशानी अब उनकी नहीं वह हमारी है।
- जब समाज दृढ़ होगा, सत्य की विजय होगी जब एकता और समान व्यवहार और ज्ञान होगा तब हमारा समाज एक नए भारत का दृढ़ निश्चय भारत का निर्माण कर पाएगा
- यदि आपका काम, स्वयं आप और आपका विचार, सत्य के साथ है तो वह आपका नहीं अपितु वह हमारा विचार होगा , क्योंकि आप भारत के चौथे स्तंभ मीडिया के साथ है
- अब आम आदमी की आवाज आम आदमी की नहीं अपितु उसके साथ हमारी भी आवाज होगी इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारे साथ शीघ्र से शीघ्र जुड़े और अपनी आवाज को एक नया आयाम दें और अपने समाज को अपने परिवार को और अपने देश को सशक्त बनाएं
- हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको कोई नया प्रयास नहीं करना केवल सामाजिक दृढ़ता संकल्प संभाग पोस्ट अभियान का एक फॉर्म भरना है

विचार न कीजिए तुरंत संपर्क करें: 9755648321

क्योंकि दृढ़ होगा समाज तो सशक्त होगा भारत और खुशहाल होगा हमारा परिवार

सत्यम,शिवम्,सुंदरम। सत्यमेव जयते

भारत माता की जय वंदे मातरम

उत्कृष्ट व मॉडल स्कूलों में प्रवेश परीक्षा आयोजित

400 सीटों के लिए 1925 विद्यार्थियों ने दी परीक्षा

खरगोन । संभाग पोस्ट

शहर के उत्कृष्ट विद्यालय सहित जिले के दो मॉडल स्कूल धुलकोट एवं झिरन्या में प्रवेश प्रक्रिया के तहत रविवार को प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। यह परीक्षा जिले के कुल 7 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। प्रवेश परीक्षा में कुल 400 सीटों के लिए 1925 विद्यार्थियों ने भाग लिया। उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य राजेंद्र पाटीदार ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्कृष्ट विद्यालय में 240 सीटें, जबकि मॉडल स्कूल झिरन्या में 80 एवं धुलकोट मॉडल स्कूल में 80 सीटें निर्धारित की गई हैं। जिले में परीक्षा आयोजन के लिए उत्कृष्ट विद्यालय, कन्या हाईस्कूल, देवी अहिल्या उमावि क्रमांक-2 खरगोन, मोतीपुरा, झिरन्या, भगवानपुरा और भीकनगांव को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। इन केंद्रों पर कुल 2118 विद्यार्थियों का पंजीयन था, जिनमें से 1925 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 193 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा सभी केंद्रों पर निर्धारित समय और दिशा-निर्देशों के अनुसार संपन्न हुई।

संस्कारों की पाठशाला

बच्चों को सनातन संस्कृति से जोड़ने का प्रयास

इंदौर । संभाग पोस्ट

नगर में संस्कारों और भारतीय संस्कृति के संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय पहल करते हुए भारतीय जनता पार्टी की नगर मंत्री श्रीमती स्वाति काशिद द्वारा नन्हे-मुन्ने बच्चों को संस्कारों का पाठ पढ़ाया जा रहा है। इस पहल के अंतर्गत सप्ताह में एक दे न उनके निवास पर बच्चों को आमंत्रित कर सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक मूल्यों एवं महापुरुषों के आदर्शों से परिचित कराया जा रहा है। श्रीमती काशिद ने बताया कि सप्ताह में एक दिन विशेष रूप से बच्चों के लिए कक्षा आयोजित की जाती है, जिसमें उन्हें गीता, रामायण, वेदों के मंत्र, चारों वेदों का महत्व तथा महान विभूतियों की प्रेरणादायी जीवन गाथाओं के बारे में सरल एवं प्रभावी तरीके से समझाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस प्रयास का उद्देश्य बच्चों के जीवन में संस्कार, अनुशासन, सद्भाव, सेवा भाव और सच्ची मानवता के बीज बोना है, ताकि वे आगे चलकर एक श्रेष्ठ, संस्कारी और जिम्मेदार नागरिक बन सकें। स्थानीय नागरिकों एवं अभिभावकों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए अत्यंत उपयोगी बताया।

APPLIED FORENSIC SCIENCE LABORATORY
Email: afslindore23@gmail.com Mobile No: +91 9366381689 +91 9977649317
SERVICES
- Handwriting Examination.
- Signature Examination.
- Fingerprint Examination.
- Deleted Data Recovery from Mobile Phones, Hard Drive.
- Laptop, Desktop Computer, Pen drive.
- Complete Examination of Digital Instrument i.e. Mobile.
- phones, Laptop, Desktop Computers, in case of Hacking.
- Voice Analysis and Voice Comparison.
- Examination of Alteration in any Documents.
- Examination of Erased Writing.
- Examination of Audio Clips and Video Clips.
- Preparation of Fingerprint Records for Corporate Offices.
- Examination of Arson Cases.
- DNA Examination for Paternity and Maternity.
- Forensic Consultancy.
- Forensic Investigation of Insurance Claims.
- Property Investigation.
- Crime Scene Investigation.
- Audio Transcription.
FORENSIC EXPERT
Rakesh Mia +91 93663 81689
Vijay Panchal +91 9977649317
Head Office: Applied Forensic Science Laboratory, 8/1, 2nd foor, Moti Tabela, Near Collectorate Office, Indore, MP, 452007
Branch Office: Chandra Forensic Science lab, Chandigarh/New Delhi

श्री रवि इत्र सुगन्ध भण्डार
गुलाब, मोगरा, चन्दन, परफ्यूम इत्यादि के थोक एवं खेरची विक्रेता
प्रोपायटर : रवि सुगन्धी
मो. 9452665448
पता: हीरानगर, मेनरोड, सुखलिया, मिलन गार्डन के पास, इन्दौर

संदीप पवार
Mob :-98260-68380
KP
॥ श्री गणेशाय नमः॥
न्यू नर्मदा ट्रेडर्स
सीमेन्ट
बालू रेती
काली रेती, गिट्टी
ईंट एवं बिल्डिंग मटेरियल के विक्रेता
4, मंगलनगर, आई.टी.आई. रोड, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, पेट्रोल पम्प के पहले, इन्दौर (म.प्र.)

रामसेवक दुबे
9406621084
पूजा बुक्स एण्ड स्टेशनर्स
CBCE स्कूल बुक्स
चिल्ड्रन बुक्स
ऑफिस स्टेशनरी
कम्प्यूटर स्टेशनरी
स्कूल स्टेशनरी एवं
गिफ्ट आयटम
6/3, सुंदर अपार्टमेन्ट, क्लर्क कालोनी चौराहा, श्री सत्य सांई बाल विनय मंदिर के सामने, इन्दौर मो.

राहुल जनरल स्टोर्स
शॉप नं. 3 मालवा मिल चौराहा, इंदौर
मो. 9977732802

पॉश कॉलोनियों में खुलेआम नशाखोरी

बायपास और सुपर कॉरिडोर भी बने हॉटस्पॉट

इंदौर। संभाग पोस्ट

इंदौर में खुलेआम सड़कों और प्रमुख चौराहों पर बढ़ती नशाखोरी की घटनाओं ने प्रशासन के सुरक्षा और जागरूकता के दावों पर सवालिया निशान लगा दिया है। शासन द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे विभिन्न अभियान धरातल पर निष्प्रभावी साबित हो रहे हैं क्योंकि नशा करने वाले लोग बिना किसी डर के सार्वजनिक स्थानों पर जमावड़ा लगा रहे हैं। हाल ही में जिला कलेक्टर शिवम वर्मा ने एक समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिए थे कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में नशाखोरी के खिलाफ व्यापक स्तर पर जागरूकता लाई जाएगी। प्रशासन की योजना के अनुसार स्कूल, कॉलेज और पंचायत स्तर पर विशेष नशामुक्ति जागरूकता समितियां गठित करने की तैयारी है, लेकिन इन प्रयासों के बीच जमीनी हकीकत यह है कि नशेड़ियों में कानून का कोई भय दिखाई नहीं दे रहा है।

बायपास और सुपर कॉरिडोर पर नशे का बढ़ता प्रभाव

शहर के बायपास और सुपर कॉरिडोर जैसे इलाके अब नशे के प्रमुख हॉटस्पॉट में तब्दील हो चुके हैं। इन सुनसान क्षेत्रों का लाभ उठाकर लोग शराब की दुकानों से शराब खरीदते हैं और फिर पास के खाली मैदानों या सड़कों के किनारे नशा करने बैठ जाते हैं। चिंताजनक पहलू यह है कि नशाखोरी का यह दौर सुबह से ही शुरू हो जाता है, जिससे वहां से गुजरने वाली महिलाओं और बच्चों को असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। खुले में नशा करने की वजह से इन क्षेत्रों में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे गंभीर आपराधिक घटनाओं की आशंका भी निरंतर बनी रहती है।

पॉश कॉलोनियों और प्रमुख चौराहों की बदहाली

नशाखोरी का यह जाल सिर्फ सुनसान इलाकों तक सीमित नहीं है, बल्कि शहर के व्यस्त और पॉश क्षेत्रों में भी फैल चुका है। बंगाली चौराहा, नंदा नगर और पीपल्याहाना जैसी विकसित कॉलोनियों में भी शराब दुकानों के आसपास लोग बेरोकटोक नशा करते हुए देखे जा सकते हैं। स्थानीय निवासियों की शिकायत है कि न तो आबकारी विभाग इन दुकानों पर सख्ती कर रहा है और न ही पुलिस प्रशासन द्वारा इन स्थानों पर कोई प्रभावी गश्त की जा रही है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और नशा करने की प्रवृत्ति से न केवल आम नागरिकों का सुकून छिन रहा है, बल्कि इससे शहर के सामाजिक वातावरण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

कलेक्टर बोले हॉटस्पॉट की लिस्टिंग की जाएगी

बढ़ती शिकायतों के बीच कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा है कि नशा समाज और युवाओं के भविष्य के लिए एक अत्यंत गंभीर खतरा है। उन्होंने जोर दिया है कि पुलिस, जिला प्रशासन, शैक्षणिक संस्थानों और नागरिक समाज को मिलकर एक साझा मोर्चे पर काम करना होगा। कलेक्टर के अनुसार, शहर के उन संवेदनशील इलाकों की सूची तैयार की जा रही है जहां नशाखोरी सबसे अधिक है। इन चिन्हित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में आने वाले दिनों में विशेष निगरानी रखी जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ताकि शहर की कानून व्यवस्था और मर्यादा बनी रहे।

शौक के लिए बाइक चोरी; चेकिंग देख भागा, हीरानगर पुलिस ने दबोचा, 5 बाइकें बरामद

इंदौर। संभाग पोस्ट

शौक के लिए बाइक चोरी करने वाले एक शातिर चोर को थाना हीरानगर पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से कुल 5 चोरी की दोपहिया वाहन बरामद की गई हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख रुपये बताई जा रही है। यह

कार्रवाई मुखबिर सूचना, तकनीकी सहायता और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई। जानकारी के अनुसार, 6 फरवरी 2026 की रात पुलिस चंद्रगुप्त सौर्य चौराहा पर वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन वह चेकिंग देखकर भागने लगा। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम मयंक उर्फ चिराग उर्फ चिमायला (22) निवासी सेठीनगर, माता मंदिर के पास, विजय नगर बताया। जांच में पाया गया कि जिस बाइक पर वह सवार था, वह थाना हीरानगर के अपराध क्रमांक 100/26 धारा 303(2) बीएनएस में चोरी की दर्ज थी और उसका वास्तविक नंबर MP37MR5557 था। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि उसने यह बाइक 2 फरवरी 2026 की रात न्यू गौरी नगर से चोरी की थी और उसे बाइक चोरी करने का शौक है। आरोपी के मेमोरेण्डम के आधार पर पुलिस ने कुल 5 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। फिलहाल पुलिस उससे अन्य वारदातों के संबंध में भी पूछताछ कर रही है। **गिरफ्तार आरोपीः** मयंक उर्फ चिराग उर्फ चिमायला, पिता गोपाल अठोनिया, उम्र 22 वर्ष, निवासी सेठीनगर, विजय नगर, इंदौर। **कार्यवाही में शामिल पुलिसकर्मीः** इस कार्रवाई में निरीक्षक सुशील पटेल, उपनिरीक्षक सुरेश भदकारे, प्रधान आरक्षक सौरभ, आरक्षक अनिल जायसवाल और आरक्षक विश्वरतन की अहम भूमिका रही।

बैंक कर्मचारी ने खुद को गोली मारी, घर खाली कराने आई थी टीम, ढाई करोड़ का था कर्ज

■ इंदौर। संभाग पोस्ट

विजय नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिनर्जी अस्पताल के पास सोमवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक को-ऑपरेटिव बैंक में कार्यरत कर्मचारी हेमंत ब्रह्मवंशी ने अपनी ही लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना शाम करीब साढ़े 5 बजे की बताई जा रही है जब मृतक अपने घर के कमरे में अकेला था।

ढाई करोड़ के कर्ज का भारी बोझ था

मिली जानकारी के अनुसार हेमंत ने अपने मकान को गिरवी रखकर बैंक ऑफ महाराष्ट्र से ढाई करोड़ रुपये का बड़ा कर्ज ले रखा था। बताया जा रहा है कि पिछले डेढ़ साल से वह बैंक की किश्तें चुकाने में असमर्थ थे। लंबे समय तक राशि जमा न होने के कारण बैंक की ओर से बार-बार नोटिस भी जारी किए गए थे, लेकिन हेमंत की ओर से उनका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था।

जब बैंक की टीम पहुंची घर, तभी गोली मारी

सोमवार को बैंक की एक टीम कानूनी प्रक्रिया के तहत मकान खाली कराने के लिए हेमंत के निवास पर पहुंची थी। जिस समय बैंक के कर्मचारी घर की पहली मंजिल पर खड़े होकर जब्ती और खाली करने की लिखा-पढ़ी की औपचारिकताएं पूरी कर रहे थे, उसी वक्त हेमंत ने नीचे अपने कमरे में जाकर आत्मघाती कदम उठा लिया। अचानक हुई गोली चलने की आवाज से घर और आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई।

डिप्रेशन का चल रहा था इलाज

विजय नगर थाना प्रभारी चंद्रकांत पटेल ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि हेमंत पिछले काफी समय से भारी कर्ज के कारण मानसिक तनाव और डिप्रेशन से जूझ रहे थे। उनके बड़े बेटे ने भी इस बात की पुष्टि की है कि उनका मानसिक उपचार चल रहा था। मृतक के परिवार में उनकी वृद्ध मां, दो बेटे और एक बेटी है, जिनका इस घटना के बाद रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने फिलहाल मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है।

सड़क के बीच में बिछी है नर्मदा लाइन,आसान नहीं होगा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाना

■ इंदौर। संभाग पोस्ट

इंदौर में छह किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की कवायद की जा रही है, लेकिन उसे बनाना इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि जब बीआरटीएस कॉरिडोर पंद्रह साल पहले बनाया गया था, तब नर्मदा लाइन सड़क के बीच वाले हिस्से में डाली गई थी। इसके अलावा हर चौराहे पर सीवरेज के बड़े पाइप भी क्रॉस हुए हैं। यदि एबी रोड पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनता है तो जगह-जगह लाइनों को शिफ्ट करना होगा। इसमें काफी समय लगेगा। बीआरटीएस निर्माण की समयसीमा दो साल तय की गई थी, लेकिन उसके बनने में पांच साल से अधिक का समय लगा, क्योंकि एबी रोड पर ट्रैफिक का दबाव काफी रहता है। ट्रैफिक को दूसरे रूटों पर भी ज्यादा डायवर्ट नहीं किया जा सकता है। यह परेशानी एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने में भी आएगी।

व्हाइट चर्च चौराहे पर पथरीली जमीन

एलिवेटेड कॉरिडोर के कॉलम बनाने के लिए जमीन में गहरी खुदाई करना होगी। इसमें सबसे ज्यादा समय गीता भवन से जीपीओ के बीच लगेगा। यहां पथरीला हिस्सा है। सीवरेज लाइन बिछाने के लिए इस हिस्से में चट्टानें तोड़ने के लिए विस्फोट का इस्तेमाल किया गया था। यहां लाइन शिफ्ट करना पड़ी तो उसके लिए भी अलग से खुदाई करना होगी।

लंबी दूरी का ट्रैफिक और होगा कम

एलआईजी से भंवरकुआं या राजीव गांधी चौराहे तक शहरवासियों को जाना हो तो वे अब रिंग रोड का उपयोग करने लगे हैं, क्योंकि खजराना चौराहा, बंगाली चौराहा, वर्ल्ड कप चौराहा, पालदा चौराहा पर ब्रिज बनने से अब रिंग रोड पर समय कम लगता है। इस मार्ग पर मुसाखेड़ी और आईटी चौराहे पर भी ब्रिज बन रहे हैं। इसके बाद ट्रैफिक और आसान हो जाएगा। एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर याचिका लगाने वाले अतुल शेठ का कहना है कि रिंग रोड के कारण वैसे ही एबी रोड के ट्रैफिक का दबाव कम हो जाएगा। इस कारण एलिवेटेड कॉरिडोर ज्यादा उपयोगी साबित नहीं होगा। पहले जब इसे लेकर सर्वे हुआ था, तब ट्रैफिक चार प्रतिशत आया था।

एरोड्रम पुलिस की बड़ी कार्रवाई

ब्राउन शुगर तस्कर गिरफ्तार

■ अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर की तस्करी में लिप्त आरोपी को थाना एरोड्रम पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार।

■ मादक पदार्थ की डिलीवरी देने से पूर्व ही पुलिस ने आरोपी को रंगे हाथों धर दबोचा।

■ आरोपी के कब्जे से 08.75 ग्राम ब्राउन शुगर (कीमत लगभग ?87,000/-) एवं एक मोबाइल फोन जप्त किया गया।

■ इंदौर। संभाग पोस्ट

शहर में अवैध मादक पदार्थों के क्रय-विक्रय एवं नशे की गतिविधियों पर अंकुश लगाने तथा इन गतिविधियों मे लिप्त आरोपियो के विरूध्द प्रभावी कार्यवाही करने हेतु पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा दिये गये है। उक्त निर्देशों तारतम्य मे अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री अमित सिंह एवं पुलिस उपायुक्त जोन-01 श्री कृष्ण लालचंदानी के मार्गदर्शन मे प्रभारी अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन-01 एवं सहायक पुलिस आयुक्त अनुभाग मल्हारगंज श्री विवेक सिंह चौहान के द्वारा थाना प्रभारी एरोड्रम निरीक्षक श्री तरुण सिंह भाटी व उनकी टीम को मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्देशों पर कार्यवाही के दौरान पुलिस टीम को दिनांक 08.02.2026 को रात्रि लगभग 01:30 बजे थाना क्षेत्र में भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि गणेश धाम, सुखदेव विहार कॉलोनी के पास एक व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर की डिलीवरी देने के लिए खड़ा है। सूचना की तस्दीक करते हुए पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मुखबिर की निशादेही पर बताए गए स्थान पर दबिश दी गई, जहाँ एक संदिग्ध व्यक्ति खड़ा मिला। पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध से पुछताछ करते हुए विधिवत तलाशी लेने पर उसकी पेंट की पिछली जेब से एक पॉलिथीन में रखा अवैध मादक पदार्थ बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम सुमित पथरोड़ उम्र 24 वर्ष, निवासी 112 पंचवटी नगर, 60 फिट रोड, इंदौर बताया। पुलिस टीम द्वारा आरोपी को थाना लाकर तौल करने पर कुल 08.75 ग्राम ब्राउन शुगर, अनुमानित कीमत रु. 87,000/- पाई गई। आरोपी के विरुद्ध थाना एरोड्रम पर अपराध क्रमांक 078/2026, धारा 08/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक तरुण सिंह भाटी, उप निरीक्षक नरेन्द्र रघुवंशी, सहायक उप निरीक्षक मुकेश परमार, आर. 1319 राकेश, आर. 1064 नवीन, आर. 2347 विपेन्द्र, आर. 3493 अजय एवं आर. 22 आनंद सिंह की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।

पुलिसकर्मी की पत्नी ने की खुदकुशी, सुबह पति ने फंदे पर लटका देखा पांच साल पहले हुई थी शादी

■ इंदौर। संभाग पोस्ट

शहर में पदस्थ एक पुलिसकर्मी की पत्नी ने आत्महत्या कर ली। पति सुबह उठे तो उन्होंने अपनी पत्नी का शव फंदे पर लटके देखा। महिला ने आत्महत्या क्यों की, इसकी वजह का पता नहीं चला है। पुलिस को कमरे से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला। बता दें, शैलेंद्र जादौन इंदौर पीटीएस में प्रधान आरक्षक हैं। वे मूलतः मुरैना के रहने वाले हैं, लेकिन कुछ वर्षों से इंदौर के पीटीएस परिसर में रह रहे थे। उनकी पत्नी स्नेहा जादौन ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पता चला है कि आए दिन दोनों के बीच अनबन होती थी, लेकिन मौत की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने स्नेहा का मोबाइल जब्त किया है। कई बार सुसाइड मैसेज रिकॉर्ड भी किया जाता है। पुलिस उसकी जांच कर रही है। सोमवार सुबह पति शैलेंद्र ने पत्नी को फंदे पर लटका देखा तो पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने मामला जांच में ले लिया है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। स्नेहा और शैलेंद्र की पांच साल पहले शादी हुई थी। दोनों को एक तीन साल का बच्चा है। शैलेंद्र के भाई सत्येंद्र भी पुलिस में होकर संयोगितागंज थाने में पदस्थ हैं। स्नेहा के पिता आर्मी से रिटायर्ड हैं।

कार्यालय पताः 201, दूसरी मंजिल, इंदौर प्रेस क्लब परिसर, एम.जी. रोड, (जिला न्यायालय के सामने), इंदौर (म.प्र.),

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक नवीन गलकर द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं ए-119, वीणा नगर, सुखलिया, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादकः नवीन गलकर, मो. 9009919948